शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार मीमांसा
मध्यप्रदेश

दो लाख छात्रों को नहीं मिली स्कॉलरशिप

पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति अटकी, नहीं जमा कर पा रहे कॉलेज फीस

भोपाल/इंदौर • डीबी स्टार

प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले पिछड़ा वर्ग के करीब दो लाख छात्रों के सामने अगली कक्षा में प्रवेश को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार 80 से 100 फीसदी तक छात्रवृत्ति देती है, लेकिन पिछले शिक्षा सत्र की राशि विद्यार्थियों को अब तक नहीं मिली है। इस देरी के चलते निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के सामने अगली कक्षा में प्रवेश के लिए फीस जुटाना मुश्किल हो रहा है, जबकि नियमानुसार यह राशि प्रवेश के महीनेभर में मिल जाना चाहिए थी। इन विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का लाभ उनके परिवार की वार्षिक आय, शिक्षण संस्था, कोर्स, फीस आदि पर निर्भर करता है। विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपए कम होने पर उसे फीस की 100 फीसदी राशि मिलती है। छह लाख रुपए तक आय होने पर 80 प्रतिशत राशि मिलती है। भले ही वह निजी या सरकारी कॉलेज में पढ़ता हो।

ये है नियम : विद्यार्थियों को पहले खुद देना पड़ती है फीस

छात्रवृत्ति को लेकर सरकार का नियम ही बाधा बन गया है। नियमानुसार प्रथम वर्ष से लेकर पीजी कोर्स तक की फीस पहले छात्रों को ही जमा करना होती है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार संबंधित विद्यार्थी को पात्रता अनुसार फीस की राशि लौटाती है। गौरतलब है कि जिन विद्यार्थियों ने पिछले साल फीस जमा की थी, उन्हें राशि अब तक नहीं मिली है, जबकि परीक्षा फॉर्म भरने की एक बार की अंतिम तारीख (21 नवंबर) निकल चुकी है। हालांकि सरकार ने इसे 21 दिसंबर कर दिया है।

छात्रवृत्ति के दो अरब रु. से ज्यादा मिलना हैं छात्रों को

भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर जिलों में विद्यार्थियों की संख्या 15 से 25 हजार है। वहीं इंदौर जिले में 55 हजार से अधिक ओबीसी विद्यार्थियों के करीब 60 करोड़ रुपए अटके हैं। अन्य जिलों में पांच से 10 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। प्रदेश में यह आंकड़ा दो अरब रुपए से अधिक है। इनमें स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर तक के विद्यार्थी शामिल हैं।

कोरोना के कारण देरी हुई

कोरोना के कारण छात्रवृत्ति देने में कुछ देरी हुई है, थोड़ा-थोड़ा कर राशि बांट रहे हैं। जल्द ही प्रत्येक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिल जाएगी।

सुमित रघुवंशी, संयुक्त संचालक, पिछड़ा वर्ग

10वीं, 12वीं की नियमित कक्षाएं, 9 व 11वीं की हफ्ते में 2 दिन

भास्कर संवाददाता | सीहोर

हाईस्कूल व इंटर के छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अगले सप्ताह से नियमित कक्षाएं लगाने की प्लानिंग की जा रही है। 4 दिसंबर को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह विचार किया गया है। 10वीं-12वीं की परीक्षाएं नियत समय पर शुरु होंगी। विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं बिगड़े इसलिए एक सप्ताह बाद कक्षाएं शुरु की जाएंगी। हालांकि 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को स्कूल में उपलब्ध स्थान के आधार पर सप्ताह में 2 या 3 बार नियमित कक्षाएं लगाई जाएंगी। हालांकि यह निर्णय विद्यालय प्रबंधन को ही लेना है। यही नहीं जरूरत पड़ने पर एक कक्षा को 2 सेक्शन में बांट सकते हैं। हालांकि विद्यार्थियों को स्कूल जाने के लिए पालकों की सहमति जरूरी होगी।

बता दें कि 1 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले हाईस्कूल व इंटर के छात्रों का कोर्स कवर कराने के लिए जिले के 124 हाईस्कूल व 108 शासकीय हायर सेकेंड्री स्कूलों में अब 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं कक्षाएं लगाने की वयवस्था की जाएगी। ताकि दिसंबर से लेकर जनवरी व फरवरी महीने में कोर्स कवर कराया जा सके। चूंकि नवमीं व 11वीं कक्षाओं के छात्रों को वार्षिक परीक्षा में जनरल प्रमोशन देने की तैयारी है इसलिए उनकी क्लास सप्ताह में दो या तीन दिन दिन ही लगेगी। जिला शिक्षा अधिकारी एसपी बिसेन के अनुसार छात्र-छात्राएं अपने पाठ्यक्रम के डाइट्स क्लियर करने के लिए माता-पिता की सहमति लेकर स्कूल आएं। स्कूल में कोविड-19 के नियमों का पालन शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों के लिए अनिवार्य है। वहीं नई व्यवस्था में स्कूल शिक्षा विभाग ने तय किया है कि स्कूल में 1 से 8 तक कक्षाएं बेशक नहीं लगेंगी लेकिन प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को नियमित रूप से स्कूल आना होगा। इसमें लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हाईस्कूल के छात्रों पर रहेगा ज्यादा फोकस

ऐसा माना जा रहा है कि हायर सेकंडरी के छात्र-छात्राएं कोचिंग जाने के कारण सरकारी स्कूलों में नियमित रूप से कम आएंगे। इसलिए हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं का कोर्स कवर कराने के लिए उनके अध्यापन पर अधिक फोकस रहेगा। क्योंकि हाईस्कूल रिजल्ट सुधरने का असर आगामी समय में हायर सेकंडरी के रिजल्ट पर दिखाई देता है।

परीक्षा फार्म भरने की तिथि एक महीने बढ़ाई

कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईस्कूल व इंटर के परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि को एक महीने बढ़ाकर 25 दिसंबर कर दिया है। पहले अंतिम तिथि 25 नवंबर घोषित की गई थी।

बीयू में वंचित छात्रों के ओपन बुक एग्जाम शुरू, 680 पेपर अपलोड

यूपी, पीजी के विद्यार्थी 15 तक जमा करेंगे उत्तर पुस्तिका

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की सितंबर में ओपन बुक पैटर्न की परीक्षाओं से वंचित करीब पांच हजार विद्यार्थियों की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है।

बीयू ने मंगलवार सुबह आठ बजे बीकाम, बीएससी, बीए, बीबीए, बीसीए, बीएससी होम साइंस और बीकॉम ऑनर्स के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित करने के लिए 680 पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। विद्यार्थियों ने पेपर डाउनलोड करना भी शुरू कर दिए हैं। पूर्व की परीक्षा से वंचित छात्र अपने प्रवेश पत्र स्टूडेंट इंफार्मेशन सिस्टम (एसआईएस) से लोड कर सकेंगे। परीक्षार्थियों को 250 शब्द में प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। यूजी-पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कल होंगी।

विद्यार्थी 14 और 15 दिसंबर को सुबह दस से शाम पांच बजे तक उत्तर पुस्तिकाएं जमा करेंगे। विद्यार्थी बीयू में कापी जमा नहीं करने की दशा में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के उपकुलसचिव (गोपनीय शाखा) के पते पर 15 दिसंबर तक स्पीड पोस्ट या रजिटर्ड डाक से भेज सकते हैं।

तो चली जाएगी 30 हजार कर्मचारियों की नौकरी

कोरोना संक्रमण के चलते निजी शिक्षण संस्थानों पर छाया संकट

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

कोरोना संक्रमण के डर से प्रदेश में अब भी सरकारी के साथ ही निजी कॉलेज और स्कूलों में अभी ताले डले हुए हैं। इसके चलते यह क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अगर सही स्थिति आगे भी जारी रही, तो इन संस्थाओं में कार्यरत तीस हजार कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आना तय है। इसके चलते एसोसिएशन ऑफ टेक्नीकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट (एटीपीआई) ने प्रदेश के प्रोफेशनल कॉलेजों को खोलने की मांग की है। इसके लिए एटीपीआई के चेयरमैन केसी जैन और सचिव अनुपम चौकसे के नेतृत्व में कॉलेज संचालकों ने गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा से भेंट कर कॉलेज खोलने की मांग की है।

मिश्रा ने इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान एटीपीआई ने उन्हें मुख्यमंत्री के नाम का एक मांग पत्र भी दिया है। जिसमें कहा गया है कि कक्षाएं शुरू न हो पाने की वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी तरह से कॉलेज बंद रहने की वजह से प्रदेश के निजी तकनीकी कॉलेजों में कार्यरत 30 हजार फैकल्टी व नॉन टीचिंग स्टॉफ की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। अगर जल्द ही कॉलेज नहीं खुले तो भविष्य में कई कॉलेज भी बंद होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे।

शैक्षणिक संस्थाएं छोड़ सब कुछ खुला

एटीपीआई का कहना है कि बीते 8 माह में शिक्षण संस्थान कोविड-19 की गाइडलाइन के परिपालन में बंद बने हुए हैं। बीते तीन माह में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए निर्देशों की वजह से शिक्षण संस्थाओं को छोड़ सभी तरह की गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। बाजार, होटल, कारखाने, शादी, पार्टियां, आमसभाएं, सिनेमा आदि एसओपी का पालन करते हुए खुल चुके हैं। ऐसे में कॉलेजों को भी शुरू किया जा सकता है। उनका कहना है कि पढ़ाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आसानी से कराया जा सकता है।

गाइडलाइन हो चुकी जारी

संगठन का कहना है कि यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा कॉलेज री-ओपन करने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके बाद भी प्रदेश में कॉलेज खेलने की कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की जा रही है। संगठन का कहना है कि कॉलेज नहीं खुलने से छात्रों के साथ ही आर्थिक रुप से तकनीकी शिक्षण संस्थाएं प्रभावित हुई हैं।

वेबसाइट पर बतानी होगी शिक्षकों की योग्यता

कार्यपरिषद सदस्य के सुझाव के बाद अब डीएवीवी शुरू करेगा प्रक्रिया

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। टीचिंग स्टॉफ के खाली पदों को भरने से पहले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) के विभागों को अपने यहां पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में बताना होगा। योग्यता, अनुभव और कौन-सा विषय पढ़ाने जैसी जानकारी शामिल है। विभागों को प्रत्येक शिक्षकों का बायोडाटा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना है। यह सुझाव पिछले महीने हुई कार्यपरिषद की बैठक में एक सदस्य ने दिया है। उसके बाद विश्वविद्यालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसा करने से यह पता चलेगा कि किसी विषय में शिक्षकों की जरूरत है। उसके आधार पर नियुक्तियां शुरू हो सकेंगी।

विश्वविद्यालय में लगातार नियमित और सेल्फ फाइनेंस शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। फैकल्टी की कमी से जूझ रहे ज्यादातर विभाग अतिथि विद्वानों के भरोसे चल रहे हैं। नवंबर में हुई कार्यपरिषद में विवि की तरफ से अतिथि विद्वानों को रखने पर जोर दिया। इस बीच कुछ सदस्यों ने कहा कि विभागों में कितने शिक्षक है, जिसमें नियमित, सेल्फ फाइनेंस, संविदा और अतिथि विद्वान शामिल है। कौन-कौन शिक्षक कितने विषय कक्षाओं में पढ़ाना है। रिसर्च के लिए कितना समय दिया जाता है। इन सभी के बारे में सदस्यों ने पूछा। बैठक में प्रो. मंगल मिश्रा ने कहा कि शिक्षकों का बायोडाटा वेबसाइट पर दिया जाए। इसे लेकर बाकी सदस्यों ने भी अपनी सहमति दे दी। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रत्येक विभाग को शिक्षकों की जानकारी जुटाने और बायोडाटा को अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। कुलपति डॉ. रेणु जैन ने कहा कि सदस्य के सुझाव को गंभीरता से लिया जाएगा। प्रत्येक विभाग की वेबसाइट पर एक-एक शिक्षक का बायोडाटा रखा जाएगा। यहां तक विवि के मुख्य वेब पेज पर सभी एचओडी के बारे में उल्लेख करेंगे।

दो सदस्यों को छोड़ सभी का कार्यकाल खत्म

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष का पद डेढ़ साल से खाली, नवंबर में दिया था विज्ञापन

प्रदेश टुडे, संवाददाता भोपाल

महिला एवं बाल विकास विभाग के विज्ञापन के डेढ़ साल बाद भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं हो सकी। इतना ही नहीं आयोग के ज्यादातर सदस्यों का भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। यह स्थिति प्रदेश में तब है जब बाल अपराध चरम पर है और प्रदेश के विभिन्न इलाकों से नाबालिक बच्चों की तस्करी की जा रही है। अभी ताजा मामला प्रदेश के राजगढ़ जिले का सामने आया है। जहां तस्कर बच्चों को दूसरे प्रदेशों में ले जाकर नीलामी करते हैं। ठीक ऐसे ही मामले कुछ दिन पूर्व प्रदेश के अन्य जिलों से भी सामने आए थे।

3 साल के लिए होता है पद

आयोग अधिनियम 2005 की धारा 7 के अनुसार अध्यक्ष का पद 3 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक कार्यकाल रहेगा। हालांकि कदाचरण पर इसके पहले भी हटाया जा सकता है।

आयोग की स्थिति

आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा कार्यकाल मार्च 2019 में समाप्त हो चुका है। कुछ सदस्यों का कार्यकाल अक्टूबर में खत्म हो गया। वर्तमान में ब्रजेश चौहान सहित एक और सदस्य कार्यरत हैं। इनका भी कार्यकाल दिसंबर और फरवरी में समाप्त होने वाला है।

कार्यपालन यंत्री के 11 खाली पदों को भरने इंजीनियरों ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

6 साल की अवधि पूरी करने वाले मूल विभाग के इंजीनियरों के प्रमोशन की उठी मांग

प्रदेश टुडे संवाददाता, भोपाल

नगर निगम भोपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कार्यपालन यंत्री के खाली 11 पदों को भरने के लिए निगम आयुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए छह साल की कार्यावधि पूरी करने वाले निगम के मूल विभाग के इंजीनियरों के प्रमोशन की मांग की गई है। एसोसिएशन के सचिव एसएन दुबे ने आरोप लगाए हैं कि नगर पालिका निगमों के सेट-अप प्लान क ा पालन नाह ी किया जा रहा है।

सहायक यंत्री के पद पर जिन्होंने 6 वर्ष की कार्यावधि पूरी कर ली है। उन सहायक यंत्रियों को वरिष्ठता के क्रम के कार्यपालन यंत्री के प्रभार पर नहीं दिया जा रहा। जबकि नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी किए गए सेट-अप अनुसार कुल 14 कार्यपालन यंत्री के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 3 पद भरे हुए हैं। 11 पद वर्तमान में खाली हैं। इनमें नगर निवेशकों के कुल 4 पद हैं, जो रिक्त हैं। जिसमें से नगर निवेशक के दो पद नगर निगम के मूल इंजीनियरों से भरे जाना है। एसोसिएशन सहायक यंत्री अनिल कुमार साहनी और आरएच जैदी को नगर निवेशक के रिक्त पदों पर प्रभार दिए जाने की मांग कर रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद मालवीय का कहना है कि यह मामला लंबे समय से पेंडिंग है। इस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

गत वर्ष जुलाई में 64 पेपर की कराई गई थी दोबारा परीक्षा

मंत्री नरोत्तम और यादव लेंगे फर्जी डिग्रीधारी जजों के रिजल्ट पर एक्शन

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (एनएलआईयू) में फर्जीवाड़ा करने वाले सवा दो सौ विद्यार्थियों के रिजल्ट प्रभारी चीफ जस्टिस संजय यादव, विधि मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और उच्च शिक्षामंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने रखे जाएंगे। इसमें भी विद्यार्थी फेल होते हैं, तो सामान्य परिषद की बैठक में उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा

प्रदेश टुडे संवाददाता, भोपाल

एनएलआईयू से 2003 से 2014 तक करीब सवा दो सौ विद्यार्थियों ने फर्जीवाड़ा कर डिग्रियां हासिल की हैं। उनकी दोबारा परीक्षा कराकर रिजल्ट तैयार हो चुके हैं। ये रिजल्ट सामान्य परिषद की बैठक में रखा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के प्रभारी मुख्य न्यायाधीश संजय यादव करेंगे। वहीं, विधि मंत्री डॉ. मिश्रा और उच्च शिक्षामंत्री डॉ. यादव भी शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एनएलआईयू परिषद की बैठक की तिथि निर्धारित नहीं कर सका है। बैठक में सवा सौ दो विद्यार्थियों के रिजल्ट रखे जाएंगे। इसमें विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यहां तक उनकी डिग्री निरस्त की जाएगी। फर्जी डिग्री लेने पर विद्यार्थियों की न्यायाधीश की कुर्सी छिनेगी। वहीं, वकील की हाईकोर्ट से मिली सनत तक निरस्त कर दी जाएगी। हालांकि रिजल्ट को लेकर सभी फर्जी डिग्रीधारी विद्यार्थियों में उत्सुकता है।

प्रदेश टुडे एजुकेशन

13 जज के रिजल्ट भी शामिल

फर्जीवाड़ा कर विद्यार्थियों ने न्यायाधीश की नौकरी तक हासिल कर ली है। इसमें 13 जजों के रिजल्ट भी शामिल हैं। इसके साथ शेष विद्यार्थी वकील तक बन गए हैं। यहां तक कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में विधि अधिकारी के पद पर आसीन हो चुके हैं। बैठक में हाईकोर्ट के पूर्व जज अभय कुमार गोहिल और तत्कालीन रजिस्ट्रार गिरिबाला सिंह की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। वहीं पूर्व जज गोहिल की रिपोर्ट ने सिस्टम को बदलने के साथ उसमें कई सुधार की अनुशंसा की थी।

64 विषयों के हुए थे पेपर

एनएलआईयू से 2003 से 2014 तक डिग्री में फर्जीवाड़ा कर विद्यार्थियों नौकरियां हासिल कर ली हैं। फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद एनएलआईयू ने गत वर्ष छह जून से 11 जुलाई तक दोबारा से 64 पेपर की परीक्षाएं कराई थी, जिसके मूल्यांकन में काफी सतर्कता रखी गई है, ताकि दोबारा किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं हो सके।

यह हैं परिषद में सदस्य

सामान्य परिषद में 19 सदस्य होते हैं। इसमें करीब 11 राज्य सरकार और अफसरशाही से आते हैं। इसमें सीएस इकबाल सिंह बैस, पीएस लॉ सत्येंद्र कुमार सिंह, पीएस फायनेंस मनोज गोविल, मंत्री विधि और उच्च शिक्षा, हाईकोर्ट संजय यादव और सतीश शर्मा, एडवोकेट जनरल पुष्पेंद्र कौरव, स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष विजय चौधरी, धर्मशास्त्र विधि जबलपुर कुलपति बलराज चौहान, चांसलर प्रतिनिधि विवेक तन्खा सहित अन्य सदस्य शामिल हैं।

मंत्रालय में निजी स्कूल संचालकों की स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने ली बैठक

बच्चों की फीस नहीं आ रही, निजी स्कूल के संचालकों ने मंत्री से मांगी आर्थिक सहायता

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। निजी स्कूल के संचालकों की स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंगलवार को मंत्रालय में बैठक ली। बैठक में कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में निजी स्कूलों के संचालन और उनमें आने वाली सभी समस्याओं के समाधान के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी सदस्य उपस्थित थे।

इस दौरान निजी स्कूलों ने मांग रखी कि शासन इस सत्र में 31 मार्च तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं इसलिए निजी स्कूलों को कम से कम शिक्षण शुल्क अभिभावक जमा करें, इसका आदेश जारी किया जाए। एसोसिएशन ने मान्यता नवीनीकरण पांच साल तक किए जाने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) की फीस का भुगतान तुरंत किए जाने और आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजित सिंह ने मंत्री से बताया कि कोरोना संक्रमण काल में निजी स्कूल 10 माह से बंद हैं। स्कूलों में फीस बिल्कुल नहीं आ रही है। इसके बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए समस्त कार्य करते जा रहे हैं। दूसरी ओर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा पहली से 12वीं तक की मान्यता नवीनीकरण पांच वर्ष के लिए नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग है कि विगत वर्षों की आरटीई की फीस तुरंत प्रदान कर दी जाए। इसके साथ ही हमारे विद्यालय में कार्यरत स्टाफ को आर्थिक सहायता दी जाए। विद्यालयों के बिजली के बिल एवं प्रॉपर्टी टैक्स समाप्त किया जाए और जो भी लोन विद्यालयों से संबंधित हैं, उनकी किस्तों को स्कूल खुलने तक रोका जाए। यदि एक सप्ताह में निर्णय नहीं लिया गया तो निजी विद्यालयों के संचालक अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। मंत्री ने निजी स्कूलों की सभी मांगों को सुना और जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त जयश्री कियावत सहित अन्य अधिकारी और निजी स्कूलों के संचालक उपस्थित थे।

सत्र शून्य वर्ष नहीं होगा घोषित

बैठक में मंत्री ने कहा कि इस सत्र को जीरो ईयर घोषित नहीं किया जाएगा। निजी स्कूलों के बच्चों को भी परीक्षा के आधार पर पास किया जाएगा, प्रमोशन के आधार पर पास नहीं किया जाएगा। मंत्री ने नवमी से बारहवीं तक की कक्षाएं जल्द शुरू करने की बात कही। साथ ही उन्होंने आरटीई के तहत शासन द्वारा दिए गए राशि को विभाग जल्द स्कूलों को भेजें, साथ ही अब ऐसी व्यवस्था बनेगी कि फीस की राशि सीधे स्कूलों के खातों में जाएगी।

केवल बीए, बीएससी की हो रही दूरदर्शन से पढ़ाई

दिसंबर के टाइम टेबल में बीकॉम शामिल नहीं

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

उच्च शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन से कॉलेजों की पढ़ाई कराने का दिसंबर का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसमें केवल बीए और बीएससी की पढ़ाई होगी। रिकॉर्डिंग न होने से बीकॉम को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, विभाग के पोर्टल पर बीकॉम के भी लेक्चर अपलोड हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिसंबर में कॉलेज खोले जाने का निर्णय बदल दिया है। इसी के चलते उच्च शिक्षा विभाग ने दिसंबर की कक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें सिर्फ बीए और बीएससी में प्रवेश लेने वाले पढ़ पाएंगे। दूरदर्शन के पास बीकॉम के रिकॉर्ड किए गए लेक्चर ही मौजूद नहीं हैं। कुछ वीडियो का प्रसारण पूर्व में हो चुका है।

पोर्टल पर भी सीमित लेक्चर

दूरदर्शन केवल उन्हीं वीडियो को प्रसारित करता है, जो वह स्वयं तैयार करता है। दूरदर्शन के पास बीकॉम के वीडियो नहीं हैं। साथ ही बीए, बीएससी के गिने-चुने वीडियो हैं। साथ ही विभाग द्वारा उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थान, देवी अहिल्या बाई विवि से तीन-तीन यूनिट के लेक्चर तैयार कर विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।

जितने वीडियो दूरदर्शन ने तैयार किए, प्रसारित हुए हैं

बीए, बीएससी और बीकॉम के तीन यूनिट के वीडियो पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। दूरदर्शन स्वयं के द्वारा तैयार वीडियो प्रसारित करता है। इसलिए दूरदर्शन ने बीकॉम के जितने वीडियो तैयार किए थे, वह प्रसारित कर दिए गए हैं।

–चंद्रशेखर वालिंबे, कमिश्नर, उच्च शिक्षा विभाग, मप्र

दो चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन के लिए 703 करोड़

शिवपुरी में 300, भोपाल में बनना है 2000 बिस्तरों का अस्पताल

भोपाल, निप्र

शिवराज कैबिनेट ने चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में निर्माणाधीन 300 बिस्तरीय अस्पताल के लिए पूर्व में जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 202 करोड़ 40 लाख के स्थान पर राशि 223 करोड़ 75 लाख रुपए के प्रस्ताव पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार कैबिनेट ने गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल परिसर में 2000 बिस्तरीय चिकित्सालय के लिए निर्मित होने वाले भवनों की डिजाइन नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के प्रावधानों के अनुरूप नवीन भूकंपरोधी

(शेष पृष्ठ छह पर...)

शिवपुरी की झीलों का होगा उन्नयन

कैबिनेट ने राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिवपुरी की झीलों के पर्यावरण उन्नयन एवं संरक्षण योजना के लिए अतिरिक्त तृतीय पुनरीक्षित आवश्यक राशि 19 करोड़ 55 लाख रुपए के साथ कुल राशि 111 करोड़ 55 लाख रुपए व्यय करने तथा योजना को निरंतर रखने की मंजूरी दी। इसमें केन्द्रांश 29 करोड़ 4 लाख रुपये एवं राज्यांश 82 करोड़ 51 लाख रुपए हैं।

13 मार्गों पर टोल संग्रहण की मंजूरी

कैबिनेट ने 13 मार्गों पर मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से निवेशकर्ता/ठेकेदार की नियुक्ति तक उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही टोल से प्राप्त राशि का निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि के माध्यम से उपयोग की स्वीकृति भी दी। इन 13 मार्गों में होशंगाबाद-पिपरिया मार्ग, होशंगाबाद-टिमरनी मार्ग, हरदा-आशापुर-खंडवा मार्ग, सिवनी-बालाघाट मार्ग, रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़ मार्ग, पिपरिया-नरसिंहपुर-शाहपुर मार्ग, देवास-उज्जैन-बडनगर-बदनावर मार्ग, रीवा-ब्यौहारी मार्ग, ब्यौहारी-शहडोल मार्ग, रतलाम-झाबुआ मार्ग, गोगापुर-महिदपुर-घोसला मार्ग, मलेहरा-लौंड़ी-चांदला मार्ग और चांदला-सरवई-गौरीहर-मतौंड मार्ग शामिल हैं।

प्रदेश में आईटीआई की फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान कलेक्टरों की निगरानी में ही होगा

भोपाल(आरएनएन)। पूरे प्रदेश में आरटीई फीस पूर्ति के भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे प्राइवेट स्कूल संचालकों को यह राशि कलेक्टर द्वारा पूरी निगरानी करने के बाद ही प्राप्त होगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर मौके की जांच करवाएंगे। मापदंड सही पाए जाएंगे तभी राशि मिल पाएगी। प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा राशि के लिए आए दिन किए जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर राज शिक्षा केंद्र ने स्थिति स्पष्ट की है। केंद्र की आईटीई सेल का कहना है कि इस फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान अभी तक कलेक्टरों की निगरानी में ही होता चला आया है। आगे भी यही प्रक्रिया रहेगी।

प्रदेश के प्राइवेट स्कूल संचालक पिछले 3 महीने से कर रहे हैं राशि देने की मांग

प्रतिपूर्ति की राशि उसी स्कूल को मिलेगी जिसके इधर अधिनियम के अनुसार समस्त सुविधाएं होंगी। इसके लिए बीआरसीसी और नोडल अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जाएगा। अगर बीआरसीसी गलत रिपोर्ट देता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि प्रवेश इस बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल में समस्त बुनियादी सुविधाएं जरूरी है। अधिनियम के मुताबिक इसके लिए कलेक्टर स्वयं स्वतंत्र हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने यह भी संकेत दिए हैं कि आगे बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। इसके लिए लगातार शासन स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

स्कूलों के एसोसिएशन ने कहा अब टूट रहा है धैर्य

इधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्यप्रदेश द्वारा कहा गया है कि अब धैर्य टूट रहा है। एसोसिएशन अध्यक्ष अजीत सिंह के अनुसार शिक्षा विभाग को बार-बार अनुनय विनय करने पर भी कोई असर नहीं हो रहा है। कोरोनाकाल में जहां अशासकीय विद्यालय 10 माह से बंद है। स्कूलों में फीस बिल्कुल नहीं आ रही है। इसके बाद भी अशासकीय विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए समस्त कार्य करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अधिकारी लालफीताशाही पर कायम है। बार-बार अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय विगत कई वर्षों से संचालित है एवं मान्यता प्राप्त है। हमें कक्षा पहली से 12वीं तक की मान्यता का नवीनीकरण 5 वर्ष के लिए कर दिया जाए, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड ने किया है।

आईटीआई में 10 तक प्रवेश के लिए आवेदन

भोपाल। प्रदेश के सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में खाली सीटों पर आवेदक 10 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा आईटीआई में फिर से प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ की गई है। आवेदक एमपी ऑनलाइन पर रजिस्ट्रेशन में हुई गलतियों में सुधार और नए कॉलेज का चयन, च्वॉइस फिलिंग और संस्थाओं में एडमिशन प्राथमिकता में सुधार, नए आवदेकों का रजिस्ट्रेशन आदि भी 10 दिसंबर तक कर सकते हैं। प्रवेश के लिए मेरिट सूची 10 दिसंबर को शाम 4 बजे जारी की जाएगी। प्रवेश की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

स्कूलों को किया जाएगा आरटीई फीस का भुगतान, देरी के कारणों का भी होगा निराकरण, इस वर्ष नवीनीकरण का नहीं लगेगा शुल्क

न शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग तथा सावधानियों का पूरा ध्यान रखें

परमार ने कहा कि कोविड की रोकथाम और बच्चों को हरसंभव सहायता हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य सावधानियों का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान निजी स्कूल संगठनों के पदाधिकारियों ने स्कूल संचालन में आ रही समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। मंत्री परमार ने समस्याओं का हरसंभव निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र लोकेश कुमार जाटव एवं आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री वियवान भी उपस्थित थे। बैठक में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, कोआलिटी फोरम प्राइवेट स्कूल्स हायरेस्टर्स, एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था संगठन सहित राज्य के अलग अल्पसंख्यक विद्यालयों के संघों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों का सप्ताह में एक या दो दिन स्कूल

मंत्री परमार ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूली बच्चों के अध्ययन अध्यापन और मैपिंग का कार्य सत्र के अंत तक पूरा कर लिया जाए, ताकि आरटीई फीस के भुगतान में विलंब न हो। उन्होंने स्कूली बच्चों के अभिभावकों से आग्रह किया कि कोविड के चलते जिस अवधि में निजी विद्यालय बंद रहे हैं, उस अवधि की ट्यूशन फीस का भुगतान विद्यालय संचालकों को करें।

इधर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी

इधर, निजी स्कूल संगठन एक आभासी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। यह कॉन्फ्रेंस राजधानी के सभी सत्रह क्षेत्र में स्थित होटर राजहाल में 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 1 बजे आयोजित की जाएगी।

मंत्री से हुई चर्चा

हमारी स्कूल शिक्षा मंत्री से विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक हुई है, जिसमें शासन नवीनीकरण, आरटीई का भुगतान, फीस से संबंधित स्कूल विशिष्ट रूप से शामिल, 1 से अभी तक की परीक्षाओं सहित स्कूलों के कार्य और उनकी दिक्कतों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मंत्री की ओर से आश्वासन प्राप्त हुआ है, हालांकि इस पर विभाग अमल होगा या नहीं कहना।

अजीत सिंह, प्रेस अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, भोपाल

प्राइवेट शाला द्वारा जारी फर्जी अंक सूची के कारण प्रवेश निरस्त

हटा। जवाहर नवोदय विद्यालय हटा में प्राइवेट शाला संचालक द्वारा जारी पांचवी कक्षा की फर्जी अंक सूची से प्रवेश का मामला सामने आया है। नवोदय प्रबंधन ने चैयरमेन कलेक्टर की अनुमति लेकर फर्जी अंकसूची से कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित 7 छात्र-छात्राओं के प्रवेश निरस्त कर दिए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी को प्राइवेट शाला की मान्यता निरस्त करने प्रतिवेदन भेजा है। प्राइवेट शाला भैंसा ग्राम का परमहंस विद्यालय है जो कि भगवानदास पटेल द्वारा भैंसा सहित हटा में भी संचालित है। इस विद्यालय द्वारा रामजी पटेल पिता विष्णु पटेल, देवेश पिता राकेश दीक्षित, कु विशाखा विश्वकर्मा पिता विजय विश्वकर्मा, शुभम गौंड पिता रमेश, मोहित लोधी पिता अवध लाल, कु श्रष्टि लोधी पिता अनिल, दशरथ अहिरवार पिता साहब अहिरवार को कक्षा पांच की अंक सूची के आधार पर 6 वी में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा ग्रामीण कोटे से दिलवाई थी। सभी सातों मेरिट में आने के कारण चयनित भी हो गए थे ।

ज्वाइनिंग देने के तीन दिन बाद अतिथि विद्वान को निकाला

स्टार समाचार | रीवा

शासकीय हाईस्कूल फुलहा का एक मामला प्रकाश में आया है जहां गेस्ट फेकेल्टी अरविंद प्रसाद पाठक को ज्वाइनिंग देने के बाद प्राचार्य ने तीन दिन बाद ही नौकरी से निकाल दिया। गेस्ट फेकेल्टी ने इस बात की शिकायत कलेक्टर से की है और न्याय की मांग की है।

दरअसल फुलहा स्कूल में अतिथि शिक्षक वर्ग-2 गणित विषय के पद पर रहे अरविंद प्रसाद पाठक को 4 दिसम्बर 2020 को प्राचार्य द्वारा स्कूल बुलाया गया और उपस्थिति रजिस्टर में सिग्नेचर कराकर ज्वाइनिंग कराई गई। मगर 7 दिसम्बर को स्कूल बुलाकर प्राचार्य केपी प्रजापति द्वारा उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और यह कारण बताया गया कि पिछले सत्र में उनके द्वारा पढ़ाई गई कक्षा में गणित का रिजल्ट 30 प्रतिशत से कम रहा है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 30 प्रतिशत से कम रिजल्ट लाने वाले अतिथि विद्वानों को नौकरी से पृथक करने का नियम है। ऐसे में अतिथि विद्वान ने जब अभिलेखों की जांच की तो पता चला कि उनके विषय का रिजल्ट 30 प्रतिशत से कम नहीं बल्कि 41.5 प्रतिशत है। गणित में पढ़ने वाले 65 बच्चों में से 27 पास हुए हैं और विभाग को जो जानकारी भेजी गई है उसमें त्रुटिवश 17 बच्चों को पास दिखाया गया है। इसी के आधार पर अतिथि विद्वान को नौकरी से बाहर निकाल दिया।

इस मामले में दो गड़बड़ियां नजर आई हैं। पहली तो विभाग को गलत जानकारी भेजना और दूसरी गलत जानकारी के आधार पर अतिथि विद्वान को नौकरी से पृथक कर देना। ज्ञात जो कि बीच सत्र में अतिथि विद्वानों को निकाला नहीं जा सकता और राज्य सरकार का भी यह स्पष्ट आदेश है कि पुराने अतिथि विद्वानों को ही काम पर रखा जाए। ऐसे में प्राचार्य ने नियम विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम दिया है ऐसी शिकायत कलेक्टर को पत्र लिखकर की गई है साथ ही आवेदक ने जन सुनवाई में भी शिकायत दर्ज की है और यह मांग उठाई कि प्रार्थी को पुनः उसी स्कूल में ज्वाइनिंग दिलाई जाए।

आइटीआइ के विद्यार्थी नहीं दे पाए परीक्षा, हंगामा

ग्वालियर (नप्र)। आइटीआइ के विद्यार्थियों ने मंगलवार को उस वक्त हंगामा कर दिया, जब वह आनलाइन परीक्षा नहीं दे पाए। देर शाम कॉलेज का स्टाफ पहुंचा और विद्यार्थियों को फिर से पेपर कराने का आश्वासन दिया।

आइटीआइ हिंदी शॉर्ट हेंड का मंगलवार को आनलाइन पेपर था। परीक्षा सेंटर पर विद्यार्थी दोपहर में पहुंच गए। उन्हें प्रवेश भी दे दिया गया, लेकिन जब उन्हें कंप्यूटर पर बिठाया गया तो किसी का इंटरनेट नहीं चल रहा था तो किसी का की बोर्ड खराब था। कनेक्टिविटी भी नहीं मिल रही थी। रायरू के सेंटर पर परीक्षा देने गए अभय सविता ने बताया कि इस बार से परीक्षा आनलाइन हुई है। कंप्यूटर नहीं चलने से पेपर नहीं दे पाए। इस सेंटर पर अंचल के विद्यार्थी आए थे, उन्हें घर भी लौटना था। हालांकि फिर से पेपर कराने का आश्वासन दिया है। इस मामले में नोडल अधिकारी व आइटीआइ कॉलेज के प्राचार्य सीएल कटारे का कहना है कि परीक्षा देने में विद्यार्थियों को आई परेशानी के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। विद्यार्थियों के हित में परीक्षा का दूसरा मौका दिया जाएगा।

रिवीजन टेस्ट का परिणाम आनलाइन घोषित

ग्वालियर (नईदुनिया रिपोर्टर)। शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की तैयारी का आकलन करने के लिए 20 से 28 नवंबर तक रिवीजन टेस्ट हुए थे। जिनका परिणाम जिला शिक्षा अधिकारी विकास जाशी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान घोषित किया गया। इसमें 139 विद्यालयों के प्राचार्य, बीईओ और बीआरसीसी की मौजूदगी रही। सदस्यों ने बताया कि टेस्ट पेपर 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए गए। वहीं समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने रिवीजन टेस्ट में कुछ विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त की।

अतिथि शिक्षकों की आफलाइन नियुक्ति न करें: अतिथि शिक्षक के संबंध में कहा गया कि संचालनालय के निर्देशानुसार कोई भी प्राचार्य किसी भी अतिथि शिक्षक को आफलाइन नियुक्ति न दे। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एडीपीसी अशोक दीक्षित ने विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम राइज विद्यालयों की सत्यापन सूची को विकास खंड वार जनपद पंचायत की सामान्य सभा से अनुमोदित करा कर 10 तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करें। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में बाउंड्री वाल, अप्रोच रोड और खेल मैदान के समतलीकरण के लिए मनरेगा द्वारा कार्य कराया जाना है। उसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में 11 तारीख तक भरनी होगी। रिवीजन टेस्ट के बाद जो विद्यार्थी डी एवं ई ग्रेड लेकर आएं, उन्हें आने वाले समय में विद्यालय की कक्षाओं में आमंत्रित करें। ज्ञात हो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड की परीक्षाएं निर्धारित समय पर कराने का निर्णय लिया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों का पाठ्यक्रम 30 प्रतिशत तक कम किया गया है।

मानदेय का मसला : विश्वविद्यालय में वित्त नियंत्रक बनाम कार्य परिषद

- वित्त नियंत्रक ने कहा कार्य परिषद को मानदेय संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं

स्टार समाचार | रीवा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आज सातवें दिन भी जारी रहा। ज्ञात हो कि कल वित्त नियंत्रक प्रभार लेने के बाद मंगलवार को भी विश्वविद्यालय नहीं आए और अपने निवास पर ही कुछ फाइल मंगवाकर हस्ताक्षर किए। अतिथि शिक्षकों के मानदेय से संबंधित फाइल में उन्होंने टीप लगाया कि कार्य परिषद को यह स्वीकृत करने का अधिकार ही नहीं है। जिससे मानदेय का मामला अब सुलझने की बजाय और उलझता नजर आ रहा है। अतिथि विद्वानों का कहना है कि वित्त नियंत्रक की इस कार्यप्रणाली से अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे विश्वविद्यालय के कुलपति व कार्यपरिषद से अपने आपको ऊपर समझने लगे हैं और उनके ऊपर प्रशासन के कुछ जिम्मेदार अधिकारी भी मेहरबान हैं। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा पूरे प्रदेश में केवल अवधेश प्रताप सिंह

विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक को ही मिली हुई है। आज दोपहर बाद जब अतिथि शिक्षक कुलसचिव से मिलने पहुंचे तो पता चला वो भी कल दोपहर तक अवकाश पर चले गए, जिससे नाराज होकर संघ ने ये निर्णय लिया कि कल से आंदोलन को उग्र करते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव का घेराव किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर तालाबंदी भी की जाएगी। धरना स्थल पर आज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष व महासचिव भी पहुंचे और उन्होंने अतिथि शिक्षकों के साथ तालाबंदी में सम्मिलित होने का आश्वासन दिया।

अब अतिथि विद्वान करेंगे तालाबंदी

ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एनपी पाठक ने अतिथि विद्वानों के प्रदर्शन के पहले दिन ही उन्हें सात दिसम्बर को मानदेय दिलाने का आश्वासन दिया था। क्योंकि 7 दिसम्बर को वित्त नियंत्रक की छुट्टी समाप्त होनी थी और उन्हें काम पर वापस आना था। मगर वित्त नियंत्रक ने ज्वाइनिंग तो दे दी पर कार्यालय नहीं आए। हालांकि अतिथि विद्वानों की फाइल कार्यालय से मंगवाई मगर उसमें यह आपत्ति जता दी कि कार्य परिषद को अतिथि विद्वानों के मानदेय जारी करने संबंधी का अधिकार नहीं है। ऐसे में विश्वविद्यालय में वित्त नियंत्रक बनाम कार्य परिषद जैसा माहौल बन गया है। गौर करने वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय में कार्य परिषद सबसे बड़ी बाडी मानी जाती है। जिस पर वित्त नियंत्रक ने आपत्ति जता दी है। अतिथि विद्वानों का कहना है कि उन्हें 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है। वह अपने घर वालों का भरण पोषण कैसे कर रहे हैं वह सिर्फ वही समझ सकते हैं। अब उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें मानदेय नहीं मिल जाता और अब वह विश्वविद्यालय में तालाबंदी करने को मजबूर हो जाएंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री आज करेंगे शासकीय बरेला कॉलेज भवन का लोकार्पण

संवाददाता, जबलपुर | बरेला में स्थित शासकीय कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन बुधवार को सुबह 11 बजे उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। एक साल पहले बनकर तैयार हुए इस भवन का उद्घाटन सरकार बदलने और कोरोना संक्रमण के चलते लगातार टलता रहा। 5.40 करोड़ की लागत से तैयार हुए भवन से बरेला के अलावा मंडला जिले के छात्र-छात्राएँ लाभान्वित होंगे। डॉ. यादव का बुधवार की सुबह इन्दौर-जबलपुर एक्सप्रेस से जबलपुर आगमन होगा और दोपहर 2 बजे सोमनाथ एक्सप्रेस से भोपाल रवाना होंगे। पता चला है कि उच्च शिक्षा मंत्री के आगमन को देखते हुए मंगलवार को देर शाम तक कॉलेज प्रशासन और एडी ऑफिस द्वारा तैयारियाँ की गईं। पी-3

बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू

संवाददाता, जबलपुर। जिले के हाई और हायर सेकेण्डरी कक्षाओं की होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को लेकर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। ऑफलाइन होने वाली परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने परीक्षा केन्द्रों को बढ़ाने की योजना बनाई है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके छात्रों को परीक्षा केन्द्रों में बैठाया जा सके। सूत्रों के अनुसार 30 दिसंबर तक परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण कर दिया जाएगा।

परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण कर दिया जाएगा।

अनियमित छात्रवृत्ति की राशि तत्काल जमा हो | लोक शिक्षण संचालनालय ने अनियमित छात्रवृत्ति की भुगतान की गई राशि को तत्काल जमा कराने के निर्देश सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को दिए हैं। संचालक केके द्विवेदी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनियमित छात्रवृत्ति भुगतान की वसूली कर शासन के पास जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लिहाजा तत्काल उक्त राशि जमा कराई जाए।

खाली पद पोर्टल पर दिख रहे भरे, असमंजस में अतिथि शिक्षक

सरकारी स्कूलों में सात दिसंबर तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करनी थी पर प्रक्रिया नहीं हुई पूरी

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछले सप्ताह प्रदेश के 2700 सरकारी स्कूलों में करीब 13 हजार अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने का आदेश दिया था। सात दिसंबर तक भर्ती करनी थी, लेकिन विभाग का विषयों पोर्टल बंद होने से प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। विभाग का पोर्टल तीन साल से अपडेट नहीं है इसलिए अतिथि शिक्षक आवेदन नहीं कर पाए हैं। जिन स्कूलों में पिछले साल तक शिक्षकों के पद खाली थे, वहां पोर्टल पर भरे दिख रहे हैं। ऐसे में अतिथि शिक्षक असमंजस में हैं। उल्लेखनीय है कि अगले सप्ताह से 10वीं व 12वीं की नियमित कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। 9वीं और 11वीं की कक्षा भी सप्ताह में दो से तीन दिन लगेगी। इसलिए स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत होगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पा रही है इस मामले में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय जयश्री कियावत का कहना है कि स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

विषयों पोर्टल पर पद नहीं दिख रहे: जिन स्कूलों में अतिथि शिक्षक विगत वर्ष कार्यरत थे वे पद पोर्टल पर रिक्त नहीं दिख रहे हैं। वहीं कुछ प्राचार्यों का कहना है कि स्कूलों में पद खाली नहीं हैं, जबकि पोर्टल पर खाली पद दिख रहे हैं। पिछले साल शिक्षकों का ऑनलाइन स्थानांतरण किया गया, जब से ही पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। इस कारण असमंजस की स्थिति बन रही है।

कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं: शासकीय उमावि निशातपुरा में गणित व विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं, लेकिन पोर्टल पर पद भरे दिख रहे हैं। छोला व उमावि करोंद में अतिथि शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन पोर्टल पर भरे हुए दिख रहे हैं। इस स्कूल में गणित, संस्कृत, जीवविज्ञान, संस्कृत व अंग्रेजी के शिक्षकों के पद खाली हैं।

रीवा के कॉलेज में भ्रष्टाचार की जांच करेगा ईओडब्ल्यू

रीवा। रीवा स्थित टीआरएस कॉलेज में भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेजों को जब्त करने के लिए करीब सप्ताह भर से ईओडब्ल्यू की टीम कार्रवाई में जुटी है। ईओडब्ल्यू ने कॉलेज की जनभागीदारी मद की राशि में बंदरबाट करने के आरोप में तत्कालीन तीन प्राचार्यों सहित 19 लोगों पर एफआइआर दर्ज कर रखी है। जांच के लिए संबंधित आरोपों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। एफआइआर तो दो वर्ष में किए गए भुगतान की जांच के आधार पर की गई है, लेकिन अब घोटाला व्यापक होने से करीब दस वर्ष में हुए भुगतान के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जांच टीम एक-एक दस्तावेज की पड़ताल के बाद उसकी जब्त कर रही है। - नप्र

स्कूली छात्रों के बस्ते का वजन तय

अरविंद पांडेय • नई दिल्ली।

स्कूली छात्रों के बस्ते के वजन को लेकर अक्सर उठने वाले विवादों को सरकार ने फिलहाल खत्म कर दिया है। इसे लेकर सरकार ने नई बैग पॉलिसी तैयार की है। इसके मुताबिक स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उनके वजन के दस फीसद से ज्यादा नहीं होगा। इसके तहत पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन औसतन 1.6 से 2.2 किलोग्राम तय किया गया है, जबकि बारहवीं में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन अब औसतन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच होगा। वहीं प्री-प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए शैक्षणिक सत्र से इस पर सख्ती से अमल का निर्देश दिया है। बच्चों के बस्ते का वजन चेक करने के लिए स्कूलों में तौल मशीन रखी जाएगी। प्रकाशकों को किताबों के पीछे उसका वजह भी छापना होगा। पहली कक्षा के छात्रों के लिए कुल तीन किताबें होंगी, जिनका कुल वजन 1,078 ग्राम होगा। वहीं बारहवीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कुल छह किताबें होंगी, जिनका वजन 4,182 ग्राम तय किया गया है। पढ़ाई के लिए समय सारिणी भी बनानी होगी। छात्रों के बैग के वजन को निर्धारित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। विस्तृत सर्वे के बाद कमेटी ने इसे अंतिम रूप दिया है। स्कूली छात्रों के बस्ते के वजन को लेकर अलग-अलग न्यायालयों की ओर से भी समय-समय पर दिशानिर्देश दिए गए थे।

कूली छात्रों के बस्ते में किताबों का वजन 500 ग्राम से 3.5 किलोग्राम रहेगा, जबकि कॉपियों का वजन 200 ग्राम से 2.5 किलोग्राम रहेगा। इसके साथ लंच बाक्स का वजन भी दो सौ ग्राम से एक किलोग्राम और पानी की बोतल का वजन भी दो सौ ग्राम से एक किलोग्राम के बीच रहेगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री बोले-डीपीसी कर रहे भ्रष्टाचार, इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए

मंत्री ने निजी स्कूल संगठनों के पदाधिकारियों से की चर्चा

भोपाल, शप्र। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने निजी स्कूल संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि प्रदेश में कुछ डीपीसी भ्रष्टाचार कर रहे है। उनकी शिकायत भी है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्यवाही करने निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि भोपाल जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में 19 करोड़ आरटीई फीस भुगतान घोटाले की ईओडब्ल्यू में जांच भी चल रही है। जांच में जिन कर्मचारियों के नाम है, वह डीपीसी कार्यालय में ही काम कर रहे है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा मंगलवार को मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों और निजी स्कूल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 वायरस के संक्रमण के चलते उत्पन्न परिस्थितियों में अशासकीय विद्यालयों के संचालन और इसमें आने वाली समस्याओं के संबंध में चर्चा की। परमार ने कहा कि कोविड की रोकथाम और बच्चों को इससे बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य सावधानियों का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान निजी स्कूल संगठनों के पदाधिकारियों ने स्कूल संचालन में आ रही समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। स्कूल संचालकों ने आरटीई फीस को लेकर कहा कि राज्य शिक्षा केंद्र के नियम अनुसार भी डीपीसी कार्यालय से फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है। इस पर मंत्री ने कहा कि कुछ डीपीसी के भ्रष्टाचार कर रहे है। इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मंत्री परमार ने स्कूलों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र लोकेश जाटव एवं आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत भी उपस्थित थी। बैठक में प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन, सोसायटी फॉर प्रायवेट स्कूल्स डायरेक्टर्स, एमपी बोर्ड प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन, अशासकीय शिक्षण संस्था संगठन सहित राज्य के अन्य अशासकीय विद्यालयों के संघों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 : दो महीने आगे बढ़ी स्वच्छता की परीक्षा, भोपाल को मिला रैंकिंग सुधारने का मौका

मंत्रालय ने जारी की सूचना

भोपाल, शसं.। शहर को स्वच्छता में नंबर एक पर लाने के लिए भोपाल को दो माह का अतिरिक्त समय मिल गया है। इस समय का फायदा अगर भोपाल उठाता है तो वो पहले से बेहतर स्थिति में आ सकता है। दरअसल, सर्वेक्षण-2021 दो माह आगे बढ़ गया है। जनवरी में होने वाला फील्ड सर्वे अब मार्च में होगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने सर्वेक्षण में भाग ले रहे शहरों के संबंधित अधिकारियों को इस बारे में सूचना भेज दी है। शहर की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी भी शहर में काफी सुधार की जरूरत है। पिछली बार जिन प्रयोगों के कारण भोपाल को 7वां नंबर मिला था, उनमें से ज्यादातर अभी ठप हैं।

इनमें करना होगा सुधार .... तभी बदलेगी तस्वीर

पब्लिक टॉयलेट : शहर में पब्लिक टॉयलेट की हालत खराब है। इसे लेकर खुद निगम आयुक्त गत दो दिनों से लगातार इनका निरीक्षण कर सुधार के निर्देश दे रहे हैं। इनमें सुधार करना जरूरी है, अन्यथा ओडीएफ डबल प्लस नहीं मिलेगा और भोपाल नंबरों की दौड़ से ही बाहर हो जाएगा।

ट्रांसफर स्टेशन : छह नए ट्रांसफर स्टेशन निमार्णाधीन हैं। इनका निर्माण महीने के अंत तक हो जाए तो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था में काफी हद तक सुधार हो सकता है।

भानपुर खंती : भानपुर खंती के रिमेडेशन का काम अंतिम चरण में है। दो माह के भीतर यदि भोपाल इस काम को खत्म कर ले और 15 एकड़ में पार्क का निर्माण शुरू हो जाए तो अंकों में सुधार हो सकता है।

आदमपुर छावनी : आदमपुर छावनी में नए और पुराने कचरे की प्रोसेसिंग की गति धीमी है। फिलहाल यहां चल रहे प्रोसेसिंग के काम को अधिक मशीनें लगाकर तेज किया जा सकता है। इसके अलावा बायो सीएनजी का प्लांट लगाने के लिए कंपनी को वर्क ऑर्डर देकर कुछ नंबर मिल सकते हैं।

4 वर्ष में भी टाइपिंग परीक्षा पास नहीं की तो सेवा से बाहर होंगे

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को सरकार ने एक मौका और दिया है। इन कर्मचारियों को अब चार साल में कंप्यूटर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि चौथे साल भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, तो सरकार फिर उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी और सेवाएं समाप्त कर देगी। इस संबंध में मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रविधान है। सहायक ग्रेड-तीन के पद पर नियुक्ति के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा तथा कंप्यूटर टाइपिंग दक्षता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जो कर्मचारी पहले से टाइपिंग में दक्ष नहीं हैं, उन्हें सरकार दक्षता प्राप्त करने के लिए तीन साल का अवसर देती है। इसके बाद भी ज्यादातर कर्मचारी उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। इस नियम में सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधन कर दिया है। अब टाइपिंग दक्षता के प्रयासों को देखते हुए नियोक्ता अधिकारी संबंधित कर्मचारी को एक साल का अतिरिक्त समय दे सकेंगे। चौथे अवसर में भी कर्मचारी पास नहीं हुआ तो संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

कर्मचारियों की जानकारी मांगी : विभाग ने सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त और कलेक्टरों से ऐसे कर्मचारियों की जानकारी मांगी है, जो टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। विभाग ने दो साल के आंकड़े एक हफ्ते में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मप्र में 408 करोड़ का निवेश करेंगी जर्मन कंपनियां

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मंत्रालय में उद्योगपतियों के साथ बैठक की। बैठक में जर्मनी की मेसर्स हैटिच इंडिया कंपनी ने इंदौर के समीप स्थित औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में लगभग 280 करोड़ रुपये के स्थायी पूंजी निवेश से फर्नीचर फिटिंग निर्माण प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया, वहीं जेडएफ स्टेयरिंग गेयर इंडिया लिमिटेड ने भी पीथमपुर में ही लगभग 128 करोड़ रुपये के स्थायी पूंजी निवेश से ऑटो कंपनी निर्माण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव दिया। इन दोनों प्रोजेक्ट से प्रदेश के लगभग 750 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा।

बैठक में बताया गया कि मेसर्स हैटिच कंपनी वैश्विक बाजार में अपनी उत्पादन लागत तथा उच्च तकनीक के कारण पहचानी जाती है। जर्मन मूल की इस कंपनी की यूरोप, अमेरिका एवं एशिया में 22 उत्पादन इकाईयां स्थापित हैं। भारत में कंपनी द्वारा मेसर्स एडवेंटिज ग्रुप के साथ संयुक्त उपक्रम बनाते हुए मैसर्स हेटिच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कार्य किया जा रहा है।

संभाग के 80 कॉलेजों में डीएलएड कोर्स की 53 फीसद सीटें खाली

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। काउंसिलिंग के तीन चरण होने के बावजूद डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) कोर्स में आधी से ज्यादा सीटें खाली हैं। इंदौर संभाग में 80 कॉलेज संचालित होते हैं जहां अभी 53 फीसद सीटों पर दाखिला होना बाकी है। इन्हें भरने के लिए कॉलेज संघ ने राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र से काउंसिलिंग के अतिरिक्त चरण की मांग की है। फिलहाल केंद्र ने दिसंबर आखिरी सप्ताह में एक बार फिर विद्यार्थियों को प्रवेश का मौका देने का विचार किया है।

बारहवीं बाद होने वाले डीएलएड में बीते साल के मुकाबले काफी कम प्रवेश हुए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से विद्यार्थी कोर्स में दाखिला लेने से कतरा रहे हैं। इंदौर संभाग में करीब 80 से ज्यादा कॉलेजों में डीएलएड कोर्स संचालित होता है। लगभग सात हजार सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश देना था। सितंबर से राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र ने काउंसिलिंग शुरू की है। अब तक इसके तीन चरण हो चुके हैं, लेकिन 3300 सीटें भर पाई है। अभी कॉलेजों में 53 फीसद सीटें रिक्त है। अशासकीय शिक्षा कॉलेज संघ के पदाधिकारी अभय पांडे और गिरधर नागर का कहना है कि तीन चरणों में अभी तक 47 फीसद सीटों पर दाखिला हुआ है। इतनी कम सीटों के साथ कॉलेजों को कोर्स संचालित करना मुश्किल है। इसके लिए केंद्र से काउंसिलिंग के अतिरिक्त चरण को लेकर गुहार लगाई है, जिसमें 15-20 फीसद सीटें और भर सकती है।

बहाना या हकीकत• अवकाश तो मिला नहीं, थाने से हो गई छुट्टी, अफसरों ने किया लाइन अटैच

सिपाही ने मांगी छुट्टी, लिखा... पत्नी का साफ कहना है कि भाई की शादी में नहीं आए तो ठीक नहीं होगा

क्राइम रिपोर्टर | भोपाल

साले की शादी में जाने के लिए छुट्टी के भावनात्मक आवेदन के कारण भोपाल ट्रैफिक में पदस्थ एक सिपाही को लाइन अटैच कर दिया गया है। यह आवेदन थोड़ा रोचक था। इसमें लिखा था प्रार्थी की पत्नी का स्पष्ट कहना है कि अगर भाई की शादी में नहीं आए तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये कारनामा ट्रैफिक थाने के सिपाही दिलीप अहिरवार ने किया है। उसके साले की शादी 11 दिसंबर को होनी है। एएसपी ट्रैफिक संदीप दीक्षित को उसने 5 दिन के विशेष अवकाश के लिए आवेदन किया है। ट्रैफिक थाना प्रभारी ने इस आवेदन को डीएसपी ट्रैफिक (एडमिन) को अग्रेषित किया। सिपाही को छुट्टी देने की प्रक्रिया चल ही रही थी कि इस बीच उक्त आवेदन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आवेदन पर लिखे गए विशेष नोट पर भी अफसरों की नजर थी।

अफसर बोले.. 11 महीने में 55 दिन की छुट्टियां ले चुका है दिलीप...

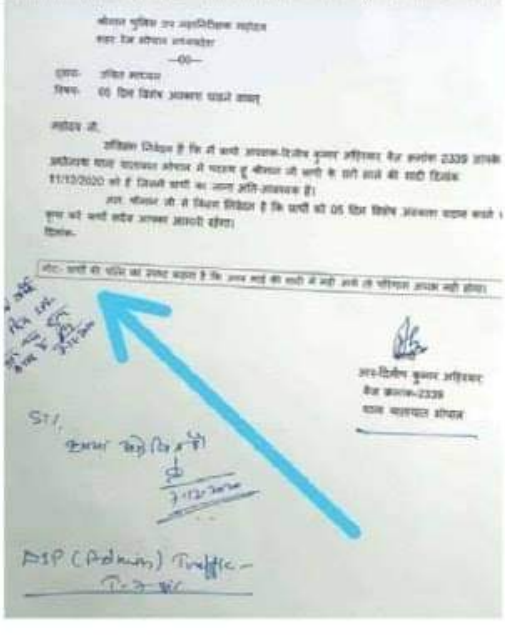

एएसपी दीक्षित ने बताया कि छुट्टी के आवेदन पर अनुचित नोट लिखना और उसे वायरल करना सेवाशर्तों को उल्लंघन है। इसे सिपाही की अनुशासनहीनता मानी गई है। उसका रिकॉर्ड देखकर पता चला कि वह 11 माह में 55 दिन की छुट्टियां ले चुका है। वह 28 नवंबर को ही छुट्टी से लौटा है। अवकाश पर निर्णय लिया जाना बाकी है।जब सिपाही से इस संबंध में बात करना चाही तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।

जांच करवाई जाएगी

*अवकाश के लिए आवेदन में विशेष नोट लिखना उचित नहीं है। सिपाही को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है। उसकी जांच करवाई जाएगी। – **इरशाद वली**, डीआईजी*

अनुशंसा • कलेक्टर को आज जाएगा प्रस्ताव, एसडीएम के नेतृत्व में 20 टीमें बनाई थी

बीपीएल सर्वे रिपोर्ट नहीं देने पर चार पटवारी, दो शिक्षक और दो निगम कर्मचारी आएंगे कार्रवाई के दायरे में

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

बीपीएल कार्डधारियों के भौतिक सत्यापन सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर चार पटवारी, दो शिक्षक व दो निगमकर्मी कार्रवाई के दायरे में आने वाले हैं। एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव कलेक्टर आशीष सिंह के जरिए बुधवार को विभाग प्रमुखों को भिजवा रहे हैं।

गौरतलब है कि वार्ड 49 में बीपीएल कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन सर्वे करने के लिए कलेक्टर ने एसडीएम त्रिपाठी के नेतृत्व में 20 टीमें गठित की थी। इनमें राजस्व, नगर निगम व शिक्षा विभाग के कर्मचारी शामिल थे। इन्हें उक्त वार्ड के 320 घरों की सर्वे रिपोर्ट एसडीएम को सौंपना थी। इनमें से अब तक 207 घरों की सर्वे रिपोर्ट एसडीएम के पास पहुंची है। ऐसे में 113 घरों की रिपोर्ट अभी भी प्रस्तुत होना बाकी है।

इधर संभागायुक्त बोले- बीपीएल सूची का शुद्धिकरण अन्य जिलों में भी हो, ताकि पात्र को उनका हक मिले

सरकारी कर्मचारी, सक्षम व अपात्र लोगों के नाम बीपीएल सूची से हटाने के लिए जिस तरह का भौतिक सत्यापन सर्वे व मुहिम उज्जैन में चल रही है वैसी ही कार्रवाई अन्य जिलों में भी होना चाहिए। ये बात संभागायुक्त आनंद कुमार शर्मा ने कही। वे मंगलवार को विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान उज्जैन में हो रहे बीपीएल सूची के शुद्धिकरण की प्रशंसा की। संभागायुक्त ने जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू को निर्देश दिए बीपीएल सूची का शुद्धिकरण कार्रवाई का प्रचार-प्रसार कराया जाए। ताकि पात्र हितग्राहियों को उनका हक मिल सके। जो लोग अपात्र पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए।

शिकायतों पर कलेक्टर ने शुरू करवाया था सर्वे

रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर टीम में शामिल पटवारी राजेंद्र सोलंकी, जगमोहन बघेल, गौरव आंजना, दर्शना राठौर, शिक्षक संजय बारा पात्रे व गिरधारी चौहान तथा निगमकर्मी संचित शर्मा व प्रमोद कश्यप के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव एसडीएम ने तैयार कर लिया है। वे प्रस्ताव बुधवार को कलेक्टर के माध्यम से विभाग के प्रमुखों को भिजवाएंगे। शिकायतों के बाद कलेक्टर सिंह ने बीपीएल कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन सर्वे करवाना शुरू किया था।

उच्च शिक्षा मंत्री ने जेयू में अकादमी भवन व साइंस कालेज में स्मार्ट क्लास का किया लोकार्पण

सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में 'अतिथि' को दी जाएगी तवज्जो

ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में माडल कालेज तैयार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। साथ ही जनभागीदारी समितियों को और सशक्त करने की दिशा में कार्य चल रहा है। इसके अलावा पीएससी के माध्यम से सहायक प्राध्यापकों की भर्ती होनी है। इस भर्ती में अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए कालेजों में एक-एक प्रोफेसर को विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के लिए प्रभारी बनाया जा रहा है। प्रभारी प्रोफेसर विद्यार्थियों को बेहतर प्लेसमेंट कैसे मिले, इस दिशा में कार्य करेंगे। यह विचार उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने व्यक्ति किए। वे साइंस कालेज में स्मार्ट क्लास के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में चाणक्य अकादमी भवन का भी लोकार्पण किया।

उच्च शिक्षा मंत्री ने अकादमी भवन के लोकार्पण के बाद संपूर्ण भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने सुंदर भवन तैयार किया है। इसमें कामर्स एंड मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह भवन सात करोड़ रुपये की लागत से तीन ब्लाक में बनाया गया है। जिसमें 16 हॉल, 28 कमरे और 17 स्टेयिंग रूम हैं। 6 हजार वर्गफीट में निर्मित इस भवन में चार ऑटिडोरियम भी बनाए गए हैं। जेयू के अकादमी भवन के लोकार्पण भवन का लोकार्पण करने के लिए मंत्री साइंस कालेज पहुंचे। उन्होंने स्मार्ट क्लास, विवेकानंद हॉल का लोकार्पण किया। जेयू के कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्यानिकी एवं खाद्यप्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने की। विशेष अतिथि के रूप में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर उपस्थित थे। जेयू में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी कुलपति प्रो. एस के शुक्ला, जेयू के कुलसचिव प्रो. आनंद मिश्रा, कार्यपरिषद सदस्य अनूप अग्रवाल, डा. मनेंद्र सोलंकी, वीरेंद्र गुर्जर, शिवेन्द्र सिंह राठौर एवं साइंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, विधायक सतीश सिकरवार, महेंद्र यादव, साइंस कालेज के प्राचार्य वीपीएस चौहान आदि मौजूद थे।

जेयू के चाणक्य अकादमी भवन का लोकार्पण करते दाएं से पहले सांसद विवेक शेजवलकर, दूसरे मंत्री भारत सिंह कुशवाह, तीसरे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। ● **नईदुनिया**

विद्यार्थियों ने मंत्री को घेरा, कहा- शराब दुकान हटाई जाए

साइंस कालेज में लोकार्पण समारोह के बाद एनएसयूआइ व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री को घेर लिया। इनके साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। विद्यार्थियों ने मंत्री को बताया कि कालेज के पास शराब की दुकान है। इस शराब दुकान को हटाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साइंस कॉलेज की बाउंड्रीवाल भी नहीं है। इससे कॉलेज में असामाजिक तत्व घुस आते हैं। कालेज की जमीन पर भी अतिक्रमण हो रहा है। मंत्री ने इन दोनों मांगों को सुनने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया।

फर्जी मार्कशीट मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा

ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद सदस्यों (ईसी मेंबर) ने सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री डा. मोहन यादव को जेयू के अंदर चल रही गड़बड़ियों के संबंध में अवगत कराया। ईसी मेंबरों ने कहा कि अधिकारियों ने चार्ट बदलकर बीएससी चतुर्थ वर्ष (परीक्षा जून 2019) की फर्जी मार्कशीटें जारी कर दीं। उसके बाद उन मार्कशीटों को निरस्त कर दिया। इस फर्जीवाड़े में अधिकारी मिले हुए हैं, उन्हें बचाया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर गड़बड़ी की जांच कराई जाएगी, किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डा. यादव जेयू के चाणक्य अकादमी भवन का उद्घाटन करने आए थे। उससे पहले कार्य परिषद सदस्य शिवेंद्र सिंह, अनूप अग्रवाल, मनेंद्र सोलंकी व संगीता कटारे ने जेयू की समस्या व गड़बड़ियों को लेकर उनसे मुलाकात की। ईसी मेंबरों ने बताया कि जेयू के बीपीएड कोर्स को मान्यता नहीं है, फिर भी 100 विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया। यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

राजा भोज मार्ग, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) 462016

दूरस्थ शिक्षा का मध्यप्रदेश का एक मात्र विश्वविद्यालय

प्रवेश सूचना 2020-21

एम.बी.ए., बी.बी.ए., बी. कॉम., एम.ए., एम.एस.डब्ल्यू., बी.ए., एम.एससी., बी.एससी., एम.एससी. (आई.टी), बी.एस.सी. (आई.टी) विभिन्न डिप्लोमा कोर्स एवं प्रमाण पत्र कोर्स **अंतिम तिथि दिनांक 31.12.2020 तथा विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक 10.01.2021**

आवेदन करने की लिंक

https://mpbou.mponline.gov.in/portal/Index.aspx

क्षेत्रीय केन्द्र : 1. **भोपाल**-0755-2492273, 2. **इन्दौर**-0731-2465689, 3. **ग्वालियर**-0751-2345559, 4. **जबलपुर**-9893151661, 9893523754 5. **रीवा**-07662-250410, 9425124312, 6. **सतना**-07672-404440, 7. **सागर**-07582-264130, 8. **उज्जैन**-0734-2526993, 9. **छिंदवाड़ा**-07162-243716 10. **होशंगाबाद**-07574-254096, 11. **बड़वानी**- 07290-222099, **अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट : www.mpbou.edu.in**

म.प्र. माध्यम/99155/2020

कुलसचिव

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

आज का इतिहास

1913	होमाई व्यारावाला - भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार का जन्म हुआ।
1761	ताराबाई - शिवाजी की पुत्री का पुणे में निधन हुआ।
1997	के शिवराम कारंत कन्नड़ भाषा के विख्यात साहित्यकार का निधन हुआ।
1625	हालैंड और इंग्लैंड के बीच सैन्य संधि पर हस्ताक्षर।
1762	ब्रिटिश संसद ने पेरिस संधि को स्वीकार किया।
1898	बेलूर मठ की स्थापना।
1998	रूस द्वारा आर्कटिक सागर में अपक्रांतिक परमाणु परीक्षण किया गया, आस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ियों शेन वार्न और मार्क वॉ ने एक भारतीय सट्टेबाज से 1994 में पाकिस्तान दौरे पर रिश्वत लेने की बात स्वीकारी।